बजट की प्रमुख बातें

सुशासन	सामाजिक आर्थिक विकास	संरचना	रोजगार

महत्वपूर्ण आंकड़े

- राजस्व प्राप्तियां: 97141 करोड़ रु.
- राजस्व व्यय: 68804 करोड़ रु.
- उपलब्ध राजस्व अधिशेष (पूंजी व्यय के लिए): 28337 करोड़ रु.
- पूंजी प्राप्तियां: 11480 करोड़ रु.
- पूंजी व्यय: 39817 करोड़ रु.
- जीडीपी में पूंजी व्यय का योगदान: 19.8 %
- जीएसडीपी में प्रत्याशित वृद्धि:7.5%

संघ राज्य क्षेत्र के संसाधन

- पात्र केन्द्रीय अनुदान: 34%
- उधार राशि: 11%
- पीएमडीपी: 9%
- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं: 14%
- संघ राज्य क्षेत्र का अपना कर राजस्व: 15%
- संघ राज्य क्षेत्र का अपना गैर-कर राजस्व: 8%
- एआरएम: 9%

संघ राज्य क्षेत्र के व्यय का पैटर्न

- संघ राज्य क्षेत्र का पूंजी/विकास संबंधी व्यय: 37%
- वेतन: 28%
- पेंशन: 8%
- ब्याज का भुगतान: 7%
- अन्य: 20%

केन्द्र सरकार की विकास संबंधी पहल:

- केन्द्रीय सहायता: 30478 करोड़ रु.
- आपदा मोचन निधि: 279 करोड़ रु.

त्वरित भर्ती अभियान हेतु श्रेणी IV की 10000 रिक्तियों के अलावा 12379 राजपत्रित एवं गैर-राजपत्रित रिक्तियों का पता लगाया गया है

राजस्व व्यय

प्रशासनिक क्षेत्र	• प्रशासनिक क्षेत्र का कुल राजस्व बजट 12460 करोड़ रु. है जिसमें से 71% तक का व्यय गृह विभाग पर खर्च किए जाने की आशा है।
सामाजिक क्षेत्र	• सामजिक क्षेत्र का कुल राजस्व बजट 21691 करोड़ रु. है जिसमें से 51% तक का व्यय शिक्षा विभाग पर खर्च किए जाने की आशा है।
अवसंरचना निर्माण क्षेत्र	• अवसंरचना निर्माण क्षेत्र का कुल राजस्व बजट 29059 करोड़ रु. है जिसमें से 60 % तक का व्यय वित्त विभाग के माध्यम से खर्च किए जाने की आशा है।
आर्थिक क्षेत्र	• आर्थिक क्षेत्र का कुल राजस्व बजट 5464 करोड़ रु. है जिसमें से 28 % तक का व्यय वन विभाग पर खर्च किए जाने की आशा है।

पूंजी व्यय

प्रशासनिक क्षेत्र	• प्रशासनिक क्षेत्र का कुल पूंजी बजट 2067 करोड़ रु. है जिसमें से 66.91 % तक की व्यय राशि गृह विभाग पर खर्च किए जाने की आशा है।
सामाजिक क्षेत्र	• सामाजिक क्षेत्र का कुल पूंजी बजट 4920 करोड़ रु. है जिसमें से 29.59 % तक का व्यय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग पर खर्च किए जाने की आशा है।
आर्थिक क्षेत्र	• आर्थिक क्षेत्र का कुल पूंजी बजट 8467 करोड़ रु. है जिसमें से 56.89 % तक का व्यय ग्रामीण विकास विभाग पर खर्च किए जाने की आशा है।
अवसंरचना निर्माण क्षेत्र	• अवसंरचना निर्माण क्षेत्र का कुल पूंजी बजट 24363 करोड़ रु. है जिसमें से 26 % तक का व्यय जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग पर खर्च किए जाने की आशा है।

विभिन्न विभागों/क्षेत्रों के प्रमुख कार्यकलाप

स्वास्थ्य क्षेत्र

एबी-पीएमजेएवाई ''सेहत'' योजना	• एबी-पीएमजेएवाई के समभिरूप एबी-पीएमजेएवाई ''सेहत'' स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के सभी 21 लाख परिवारों को प्रति परिवार 5 लाख रु. तक के मुफ्त चिकित्सा उपचार संबंधी स्वास्थ्य कवरेज हेतु किया गया।
ऑक्सीजन जनरेशन पलांट्स/मशीनरी एवं उपकरण	• कोविड-19 महामारी की वजह से मेडिकल ऑक्सीजन की अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने के लिए 227.73 करोड़ रु. की लागत से जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के सभी मेडिकल कॉलेजों, संबद्ध अस्पतालों तथा जिला अस्पतालों में 37 ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट्स की स्थापना। • विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओ के माध्यम से स्वास्थ्य संस्थानों के लिए 367.49 करोड़ रु. के मशीनरी एवं उपकरण का प्रापण किया जा रहा है।
टरशरी केयर अवसंरचना	• दो मेडि-सिटीज की स्थापना • बेमिना, श्रीनगर में 116.25 करोड़ रु. की लागत से 500 बिस्तर वाले पेडियाट्रिक अस्पताल का शुभारंभ। • लाल देद अस्पताल श्रीनगर में 132.50 करोड़ रु. की लागत से 200 बिस्तर वाले अतिरिक्त ब्लॉक का निर्माण। • बॉन एंड ज्वाइंट हॉस्पिटल श्रीनगर में 88.94 करोड़ रु. की लागत से 6 बिस्तरों वाले आईसीयू सहित 120 बिस्तरों वाली विशेषीकृत ऑर्थोपेडिक यूनिट का निर्माण।
चिकित्सा शिक्षा अवसंरचना	• उधमपुर तथा हंदबाड़ा (जिला कुपवाड़ा) में से प्रत्येक में 325 करोड़ रु. की लागत से दो नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। • श्रीनगर तथा जम्मू में प्रत्येक के लिए 120 करोड़ रु. की लागत से कैंसर संस्थान की स्थापना। • जम्मू-कश्मीर के भद्रवाह में 100 करोड़ रु. की लागत से ''इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूट मेडिसिनल प्लांट'' की स्थापना।
पैरा-मेडिकल/अन्य अवसंरचना	• अनंतनाग, बारामुला, सोपोर, गंग्याल (जम्मू) तथा किस्तबाड़ में 5 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। • मौजूदा 10 जीएनएम विद्यालयों में से प्रत्येक का 6 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से नर्सिंग कॉलेज के रूप में स्तरोनयन किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है।
	• कठुआ में 34 करोड़ रु. की लागत से आधुनिक ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना।

कृषि एवं बागवानी

कृषि उत्पाद/मैकेनाइजेशन	• वर्ष 2021-22 में 15.50 करोड़ रु. के निवेश से 1 लाख क्विंटल बीजों का वितरण करके 7.50 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। • वर्ष 2021-22 के दौरान 91.27 करोड़ रु. की राशि के प्रावधान से 2500 पम्प सैट, 750 बोरबेल तथा फील्ड चैनलों के निर्माण जैसी अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करके 87750 हैक्टेयर भूमि को कवर करते हुए 25000 किसानों को लाभ प्रदान किया जाएगा। • वर्ष 2021-22 में 65.81 करोड़ रु. की राशि के प्रावधान से खेती संबंधी मशीनरी प्रदान करके 30000 किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। • वर्ष 2021-22 के दौरान 1 करोड़ रु. के प्रावधान से दो मण्डियों की स्थापना करके 25000 किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। • वर्ष 2021-22 के दौरान 26 करोड़ रु. के प्रावधान से 35000 किसानों की क्षमता संवर्धन हेतु उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। • जर्मप्लाज्म प्रोडेक्शन जैसे सूचकांकों के माध्यम से कृषि विश्वविद्यालयों की मान्यता संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसानों की सहायता हेतु 2.50 करोड़ रु. की राशि का प्रस्ताव किया गया है। • सुनिश्चित सिंचाई सुविधा की वजह से केसर की खेती के उत्पादन में और वृद्धि होने की आशा है।
रेशम कीट उत्पादन	• अवसंरचना सपोर्ट सहित बेहतर गुणवत्ता के सिल्क बार्म सीड्स के विकास, उत्पादन/वितरण हेतु 7.25 करोड़ रु. की राशि का प्रावधान किया गया।
बागवानी	• वर्ष 2021-22 में 120 हैक्टेयर भूमि को कवर किए जाने के लक्ष्य के साथ हाइडेंसिटी प्लानटेशन के तहत एरिया का विस्तार। • वर्ष 2021-22 में ड्राई तथा ताजे फलों के निर्यात का लक्ष्य 22.30 लाख मीट्रिक टन (22 लाख मीट्रिक टन ताजे फल तथा 0.30 लाख मीट्रिक टन ड्राई फ्रूट) है। • वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के प्रयास किए जाएंगे। • वर्ष 2021-22 में सी. ए स्टोर्स की स्थापना के लिए अतिरिक्त सब्सिडी/सहायता के रूप में 74.55 करोड़ रु. की राशि का प्रावधान किया गया है ताकि आगामी तीन वर्षों में सीए स्टोर्स की 4 लाख मीट्रिक टन क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

पशु एवं भेड़ पालन/मत्स्य पालन

भेड़ पालन	• इंटीग्रेटिड शीप डेवलेपमेंट स्कीम को लागू करके 2000 यूनिटों की स्थापना करते हुए 27500 भेड़ों/बकरियों को इन यूनिटों में रखकर तथा 5 लाख किलोग्राम मटन के अतिरिक्त उत्पादन द्वारा सैकड़ों लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किए जाने के साथ-साथ 2000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करना। • कारकास यील्ड को 18 किलोग्राम से बढ़ाकर 21 किलोग्राम तथा ऊन को 2 किलोग्राम से बढ़ाकर 2.5 किलोग्राम करने के लिए मौजूदा 5000 जानवरों के अलावा 4000 अतिरिक्त रैम/बक्स को शामिल किया जाना। • स्माल रयूमिनेंट सेक्टर में आर्टिफिशियल इन्सेमीनेशन की शुरूआत।
पशुपालन	• इंटीग्रेटिड डेयरी डेवलेपमेंट स्कीम को लागू करना जिसमें रोजगार सृजन के साथ-साथ मिल्क पूल में 20000 मवेशियों को शामिल करना। • पशुपालन करने वाले प्रगतिशील किसानों को पशुपालन स्वास्थ्य देखभाल/ब्रीडिंग सर्विस की डोरस्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल वेटरनिरी क्लीनिकों को चालू करना।
कुक्कुट पालन	• जम्मू-कश्मीर पॉल्टरी नीति 2020 तथा पोल्टरी डेवलेपमेंट प्रोग्राम को लागू करके तथा 30000 लोगों के लिए रोजगार के सृजन द्वारा पोल्टरी मीट उत्पादन को 7.8 करोड़ रु. किलोग्राम से बढ़ाकर 8.5 करोड़ किलोग्राम करना।
मत्स्यपालन	• विभिन्न स्कीमों को लागू करके 21000 मीट्रिक टन के मौजूदा मत्स्य उत्पादन को **और** 1000 मीट्रिक टन **की बढ़ौतरी** करना। • देश के अन्य राज्यों में ट्राउट के निर्यात हेतु मार्केटिंग प्लेटफार्म को सुदृढ़ करना। • संघ राज्य क्षेत्र में मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए रि-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम तथा बायो फ्लोक टेक्नोलोजी जैसी नई पहलों की शुरूआत करना। • संघ राज्य क्षेत्र में बीज उत्पादन को बढ़ावा देने तथा बीजों का निर्यात करने के लिए बहु-स्तरीय प्रणाली के साथ नई हैचरीज की स्थापना तथा मौजूदा हैचरीज को सुदृढ़ करना।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण	• कच्चे/जीर्ण-शीर्ण घरों में रह रहे पात्र ग्रामीण परिवारों को पक्के घरों के रूप में आश्रय प्रदान करने के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान 117419 घरों का निर्माण कार्य पूरा किया जाना है।
हिमायत (डीडीयू-जेकेवाई)	• वर्ष 2021-22 के दौरान 39113 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और 20912 अभ्यर्थियों को रोजगार प्रदान किया जाएगा।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	• वर्ष 2021-22 के दौरान 16000 स्वयं सहायता समूहों तथा 1600 ग्राम स्तरीय संगठनों का गठन किया जाएगा। 24866 स्वयं सहायता समूहों को वर्ष 2021-22 के दौरान रिवोलविंग फंड तथा 46799 स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि प्रदान की जाएगी।
ग्रामीण अवसंरचना एवं पंचायती राज	• वर्ष 2021-22 के दौरान 130 ग्रामीण कनेक्टिविटी संबंधी कार्यों को पूरा किया जाएगा। • 700 निर्वाचित प्रतिनिधियों को एक्सपोजर-सह-प्रशिक्षण दौरों पर अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। 276 बीडीसी अध्यक्षों, **सभी** डीडी**सी** सदस्यों, 4291 सरपंचों तथा 40000 पंचों को प्रशिक्षित किया जाएगा। • वर्ष 2021-22 के दौरान 100 नए पंचायत घरों का निर्माण किया जाएगा।
मनरेगा	• मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से मनरेगा कामगारों की ऑन द स्पॉट हाजिरी दर्ज करने के लिए मोबाइल मॉनीटरिंग सिस्टम की शुरूआत की जाएगी। • लगभग 0.60 लाख कार्यों को प्रारंभ किए जाने की उम्मीद है जिसमें से 30 % जल संरक्षण संबंधी कार्यों तथा 30 % व्यक्तिगत लाभार्थी उन्मुख कार्यों को पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। • 3.50 करोड़ व्यक्ति दिन का उत्पन्न किया जाएगा।

विद्युत क्षेत्र

विद्युत उत्पादन	• किरथाई-।। (930 मेगावाट), **सावलकोट** (1856 मेगावाट), उरी-। स्टेज-।। (240 मेगावाट) तथा दूलहस्ती स्टेज-।। (258 मेगावाट) जैसी नई हाईड्रो इलेक्ट्रिक विद्युत परियोजनाओं को प्रारंभ करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। • 850 मेगावाट के नए संयुक्त उपक्रम रेटले बिजली परियोजना के लिए तौर तरीकों को अंतिम रूप दिया गया है।

सिस्टम इम्प्रूवमेंट	• पीएमडीपी के तहत सभी शहरी उपभोक्ताओं के लिए 2 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाने के कार्य को जून 2021 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। • वर्ष 2021-22 के दौरान ट्रांसफॉर्मर कटआउट लगाए जाने का कार्य सभी फीडरों को सौंप दिया गया है। • समस्या के निराकरण हेतु 24x7 ई-कस्टयूमर केयर/कॉल सेंटर की स्थापना की गई है।

विद्युत अवसंरचना	• ग्रिड लेवल पर ट्रांसफॉरमेशन क्षमता को बढ़ाने के लिए अक्तूबर, 2022 तक सभी 22 परियोजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा। • नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए पूरे संघ राज्य क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाएगी जिसके लिए पम्पोर, कालाकोट एवं कावा में भूमि की पहचान कर ली गई है। • पीएमआरपी के तहत पीजीसीआईएल द्वारा 220 किलोवाट और 132 किलोवाट ग्रिड स्टेशनों के बीच कुशल एवं भरोसेमंद संचार व्यवस्था हेतु लागू की जाने वाली ऑप्टीकल ग्राउंडेड वायर परियोजना को शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा।

पर्यटन और संस्कृति

पुरजोर कैम्पेनिंग के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन करना।

सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के निवेश के माध्यम से नए पर्यटन स्थलों का पता लगाया जाएगा।

एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वाटर बेस्ड टूरिज्म एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जाएगा।

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा गोल्फ टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा।

हाई एंड पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन से संबंधित परिसंपत्तियों के नवीनीकरण एवं स्तरोन्नयन के अलावा विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

विरासत स्थलों के संरक्षण एवं परिरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा ।

त्यौहारों के कार्यक्रमों के अतिरिक्त सांस्कृति विरासत, स्थानीय फिल्म/सिनेमा/थिएटर का प्रदर्शन

जल शक्ति

जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के हरेक ग्रामीण घर में सितम्बर 2022 तक 100% पाइप जल कनेक्शन प्रदान कर दिए जाएंगे।

वर्ष 2021-22 के दौरान 19.65 लाख जनसंख्या को कवर करते हुए 3.83 लाख जल कनेक्शन मुहैया करवाए जाएंगे।

जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के योजना के तहत कवर न किए गए सभी विद्यालयों एवं आंगनवाड़ियों में जल कनेक्शन मुहैया करवाए जाएंगे।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 410 जलापूर्ति योजनाओं को पूरा किया जाएगा।

एआईबीपी-पीएमकेएसवाई के तहत मौजूदा 57 लघु सिंचाई योजनाओं को वर्ष 2021-22 में पूरा कर लिया जाएगा तथा 0.19 लाख हैक्टेयर से अधिक भूमि में सिंचाई की संभावना का पता लगाए जाने के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा।

''संगम रेफरेंस प्वाइंट पर झेलम नदी की डिस्चार्ज कैपिसिटी को 60000 क्यूसैक से बढ़ाकर 41000 क्यूसैक करने तथा पदशाही बाग **श्रीनगर** के ऑफटेक पर इसकी क्षमता को 8700 क्यूसैक से बढ़ाकर 17000 क्यूसैक किए जाने संबंधी लक्ष्य को पूरा करने के लिए ''कम्प्रीहैंसिव फ्लड मैनेजमेंट प्लान ऑफ रीवर झेलम एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज'' को शीघ्र पूरा किया जाएगा।

तबी बैराज (शेष भाग) तथा उझ मल्टीपरपज परियोजना (यूएमपीपी) संबंधी कार्य को शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा।

आवास एवं शहरी क्षेत्र

अटल मिशन फॉर रिजूविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉरमेशन (अमृत)

अमृत के तहत आगामी वित्त वर्ष के दौरान 7 परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा जिसमें पंचतीर्थी मल्टी लेवल पार्किंग, जम्मू में तवी नदी पर पांच नालों का सीवैज ट्रीटमेंट, श्रीनगर में साईकिल ट्रैक, त्रिकुटा नगर में ड्रेनेज, श्रीनगर में मल्टी लेवल पार्किंग, आईटीएमएस (इन्टेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) चरण-।।, श्रीनगर एवं जलापूर्ति योजना, रंगिल शामिल हैं।

स्मार्ट सिटी मिशन

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट सिटी/कन्वर्जेंस/पीपी मोड के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र की 40 परियोजनाओं को आगामी वित्त वर्ष के दौरान पूरा किए जाने की आशा है। इनका मुख्य उद्देश्य वाई-फाई सुविधा, स्मार्ट हेल्थ केन्द्र, ऐतिहासिक बाजारों का स्तरोन्नयन,वैंडिंग मशीनों की स्थापना, स्मार्ट क्लासरूम, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना, नदी के किनारों पर जगमग रोशनी का प्रबंध, साइकिल ट्रैक/हॉकर जोन का विकास, फ्लाई ओवरों के नीचे पार्किंग तथा खाली जगहों की व्यवस्था इत्यादि करके लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है।

सीवरेज ट्रीटमेंट

74 एमएलडी क्षमता वाले 16 नए एसटीपी की स्थापना की जानी है जो लगभग 2 लाख घरों की जरूरतों को पूरा करेंगे।

बिजली की बचत करने वाली स्ट्रीट लाइट

सभी 78 यूएलबी में पूर्ण रूप से (100%) एलईडी लाईट लगाई जाएंगी।

स्वच्छ भारत मिशन (यू) और ठोस कचरा प्रबंधन	• ओडीएफ+ कैटेगरी के स्तर को प्राप्त करने के लिए 25 यूएलबी का लक्ष्य रखा गया। • कचरे को स्रोत से ही 100% पृथक करना और डोर टू डोर कलेक्ट करना। • श्रीनगर और जम्मू में लगभग प्रतिदिन 850 मी.टन कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान करने के लिए एसडब्ल्यूएम संयंत्र की स्थापना करना। • 690 मी.टन कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान करने के लिए 76 यूएलबी में कचरे के विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना करना।

प्रदूषण को कम करना	• एनजीटी के निर्देश पर सीपीसीबी द्वारा 9 पहचान किए गए प्रदूषित नदी स्थानों के पुनरुद्धार एवं विकास के लिए वर्ष 2021-22 में 200 करोड़ रु. निर्धारित किए गए। • हाउस बोटों में हल बेस्ड बॉयो डाईजेस्टर स्थापित करना और साथ ही एअरेटर्स भी स्थापित किए जाएंगे और डी-वीडिंग मशीनें खरीदी जाएंगी।

प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)	• वर्ष 2021-22 में 25,000 मकानों के पूर्ण हो जाने की संभावना है। • वर्ष 2021-22 में 50,000 लाभार्थी मकानों को जीओ-टैग्ड किया जाएगा।

सामाजिक सुरक्षा/ राहत और पुनर्वास

कवरेज	• डीबीटी मोड के माध्यम से वर्ष 2021-22 में सामाजिक सुरक्षा स्कीमों में 100% परिपूर्णता का स्तर। • रियल टाइम मॉनिटरिंग और रिकार्डों के रख-रखाव के साथ एडब्ल्यूसी (AWCs) की मौजूदा कार्य प्रणाली को पूर्ण रूप से डीजिटाइज करने के लिए आईसीडीएस (ICDS) कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (सीएस) शुरू किए जाएंगे।

अत्यधिक कमजोर वर्ग	• वर्ष 2021-22 में बाल आश्रम, नारी निकेतन भवन और हॉफ वे होम्स का निर्माण प्रस्तावित किया जा रहा है।

कश्मीरियों प्रवासियों की राहत और पुनर्वास	• प्रधान मंत्री पैकेज के अंतर्गत कश्मीरी प्रवासियों के लिए सृजित किए गए 6000 पदों में से, 3841 पद भर लिए गए हैं और शेष पदों पर वर्तमान में भर्ती की जा रही है। • ट्रांजिट आवास की 6000 ईकाइयों में से, 1025 यूनिटों को पहले ही पूरा कर लिया गया। ट्रांजिट आवास की 1488 ईकाइयों का कार्य वर्ष 2021-22 में शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही साथ, अन्य 2444 ईकाइयों के लिए भूमि की पहचान कर ली गई। पीएम पैकेज के अन्य घटकों में आवासन, रोजगार, ऋण की माफी, नगद सहायता और निःशुल्क राशन जैसी व्यवस्था को वर्ष 2021-22 में जारी रखा जाएगा।

गुज्जर, बकरवाल और अनुसूचित जन जाति के छात्र	• गुज्जर, बकरवाल और अनुसूचित जन जाति के छात्र को डीबीटी के माध्यम से 100% संवितरण के साथ प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का 100% कवरेज। • गुज्जर/बकरवाल के लिए हॉस्टलों का निर्माण, मिल्क विलेज, लाइब्रेरी की स्थापना और सामूहिक जनजाति गांव का विकास। • अनुसूचित जन जाति के छात्रों के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों की स्थापना की जाएगी।

शिक्षा

शैक्षणिक इंफ्रास्ट्रक्चर	• 46.27 करोड़ रुपये की लागत से बराबर संख्या में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 723 आईसीटी प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। • 114.14 करोड़ रुपये की लागत से बालिकाओं के लिए 38 हॉस्टलों का कार्य पूरा किया जाएगा। • 43.33 करोड़ रुपये की लागत से 40 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) भवनों का कार्य पूरा किया जाएगा। • वर्ष 2021-22 के दौरान 245 कार्यों को पूरा किया जाएगा जिसमें मॉडल स्कूलों, अतिरिक्त क्लास रूमों, शौचालयों सुविधाओं, स्मार्ट क्लास रूम्स का निर्माण भी शामिल है। • बनिहाल, कुपवाड़ा, गूल, खिलोत्रान, माहोर, कालाकोट, हादीपोरा, सिंहपोरा (पट्टन), विलगाम (कुपवाड़ा) और **पाडर** (**किश्तवाढ़**) में 10 डिग्री कॉलेज **बिल्डिंग** का निर्माण पूर्ण। • मौजूदा डिग्री कॉलेजों में 108 अतिरिक्त क्लास रूम्स का निर्माण पूर्ण। • 10 कॉलेजों में विज्ञान प्रयोगशाला ब्लॉकों का निर्माण पूर्ण। • जीडीसी सुम्बल, पुलवामा, सौपियां में 3 ऑडोटोरियम का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा।

नामांकन और बीच में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को रोकने के लिए सुधार कार्यक्रम	• जम्मू और कश्मीर में प्राथमिक, अपर प्राथमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी लेबल में जीईआर (सकल नामांकन अनुपात) को 83.38, 72.77, 67.76 और 53.70 से बढ़ाकर क्रमशः 85.00, 74.00, 69.50 और 57.00 करने का लक्ष्य है। • जम्मू और कश्मीर में मार्च, 2022 तक हाई स्कूल स्तर पर ड्रॉप ऑउट की दर को 17.12 से घटाकर 15.00 करने का लक्ष्य है।

कौशल और ऑटोमेशन	• 1200 परम्परागत क्लास रूमों का आईटी एनेबल्ड क्लास रूमों में परिवर्तन । • शेष सभी डिग्री कॉलेजों में लाइब्रेरियों का ऑटोमेशन। • सभी डिग्री कॉलेजों में छात्र कौशल केंद्रों की स्थापना करना। • कौशल संवर्धन प्रशिक्षण (एसईटी) स्कीम के अंतर्गत 10,000 छात्रों को प्रशिक्षित करना। • 19.10 करोड़ रु. की लागत से बराबर संख्या में प्राथमिक स्कूलों में 382 कम्प्यूटर एडेड लर्निंग सेंटरों (सीएएल) की स्थापना करना। • 3.85 करोड़ रु. की लागत से बराबर संख्या में हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूलों में 77 वोकेशनल लैब की स्थापना करना।

सड़क और पुल

सुधार	• 1 अप्रैल, 2021 से जेकेपीडब्ल्यूडी ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम JKPWDOMAS (जेकेपीडब्ल्यूडीओएमएएस) का शुभारंभ जिसमें डीपीआर तैयार करने से लेकर फाइनल बिल पेमेंट तक के सभी कार्य ऑनलाइन तरीके से किए जाएंगे। • प्रत्येक जिले में गुणवत्ता नियंत्रण लैब की स्थापना • निगरानी के तंत्र को विकसित करने के लिए नेशनल लेवल कंसल्टेंट की नियुक्ति । • "थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन" प्रणाली की शुरूआत करना।

सड़क/पुल इंफ्रास्ट्रक्चर	• पीएमजीएसवाई । एवं ॥ के अंतर्गत, वर्ष 2021-22 के दौरान 4500 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य पूरा किया जाएगा और 150 **नयी** बसावटों को सड़क कनेक्टविटी दिए जाने का लक्ष्य है। • जम्मू और कश्मीर को पीएमजीएसवाई ॥। के लिए ऑनबोर्ड रखा जाएगा जिसके लिए वर्ष 2021-22 में अपग्रेडेशन के लिए 1750 किलोमीटर सड़क की मंजूरी दी जाएगी। • पीएमजीएसवाई IV के अंतर्गत, वर्ष 2021-22 तक जम्मू और कश्मीर में 100% सड़क कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए 250+ लोगों की आबादी वाली बसावटों को कोर नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य है। • शहरों और कस्बों / पीएमजीएसवाई / सीआरआईएफ / नाबार्ड के तहत 2021-22 के दौरान सड़कों की संपूर्ण 8000 किलोमीटर ब्लैक-टॉपिंग का लक्ष्य रखा गया है । • वर्ष 2021-22 में 14 पुलों का निर्माण कार्य पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है जिससे 2.85 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा।

गड्ढा मुक्त सड़कें	• 100 करोड़ रुपये का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है और पूरे जम्मू और कश्मीर में गड्ढा मुक्त सड़कें सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2021-22 में फिर से 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उद्योग

01.04.2021 से 31.03.2037 तक के लिए लागू 28400 करोड़ रुपये की कुल लागत से **"जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम"** अधिसूचित की गई है। विनिर्माण कार्य के अंतर्गत सभी पात्र इकाईयों और संबंधित प्रोत्साहन योजनाओं अर्थात **इस स्कीम के अतंर्गत कैपिटल इनवेस्टमेंट इनसेंटिव (सीआईआई), कैपिटल इन्टरेस्ट सबवेंशन (सीआईएस), गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिंक्ड इंसेंटिव (जीएसटीएलआई) और वर्किंग कैपिटल इन्टरेस्ट सबवेंशन (डब्ल्यूसीआईएस)** के अंतर्गत यथा परिभाषित इस योजना के अंतर्गत पात्र सेवा क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

इससे नए निवेश और मौजूदा उद्योगों के विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा और इससे 4.50 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर	औद्योगिक रोजगार	व्यापार संवर्धन/निवेश	प्रोत्साहन
• कैपेक्स बजट 2021-22 के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र में नई औद्योगिक संपदा के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। • 50 करोड़ रुपये की लागत से ट्रेड सेंटरस का निर्माण। • जम्मू क्षेत्र में चरकाह (सांबा), करंडी, मिर्थ घाटी, साहर **लोगेट** (कठुआ) में नई औद्योगिक संपदा के विकास के लिए 44.80 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए। • वर्ष 2021-22 के दौरान संगियोट, **कुद के पास** पहलीपोरा (लार) और चेवा (बांदीपोरा) में फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। • 20.47 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों में तीन सीईटीपी का निर्माण किया जाएगा। • 100 करोड़ रुपये की लागत से जम्मू/श्रीनगर में प्रत्येक में दो आईटी टावरों का कार्य पूरा किया जाएगा।	• 7386 लोगों को रोजगार देने के लक्ष्य के साथ वर्ष 2021-22 के लिए 25 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी वाले जम्मू कश्मीर ग्रामीण रोजगार स्रजन कार्य के अंतर्गत 1231 इकाईयों का लक्ष्य है।	• 456 निवेश प्रस्ताव/एमओयू प्राप्त हुए हैं जिनमें 23000 करोड़ रुपये का निवेश निहित है। • डोमेस्टिक/इंटरनेशनल रोड शो सहित जम्मू और कश्मीर ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट का आयोजन करने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।	• कैडिट कार्ड स्कीम के अंतर्गत 2000 को – ऑपरेटिव/स्व सहायता समूहों का कवर किया जाएगा जिससे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से 12000 लोग लाभान्वित होंगे। • कारीगर कैडिट कार्ड स्कीम के अंतर्गत कारीगरों द्वारा 2 लाख रुपये तक ऋण प्राप्त करने के लिए 7% ब्याज की आर्थिक सहायता।

रोजगार और कौशल विकास

रोबोटिक्स, डिजाइन इंजीनियरिंग, इलैक्ट्रिक वाहन रख-रखाव और मरम्मत उद्योग से संबंधित पाठ्यक्रमों, वस्तुओं के इंटरनेट, मैकेट्रॉनिक्स आदि जैसे उद्योग संबंधी पाठ्यक्रमों में तकनीकी संस्थानों के छात्रों का कौशल संवर्धन करने के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक जम्मू और राजकीय पॉलिटेक्निक बारामूला में टाटा टैक्नोलोजी के सहयोग से दो सीआईआईआईटी की स्थापना की जा रही है।

"मिशन यूथ" के माध्यम से युवाओं के उत्थान और रोजगार के लिए उनकी नियुक्तियां करना।

जम्मू और कश्मीर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से स्व-रोजगार के साथ-साथ विभिन्न बैंक प्रायोजित योजनाओं और यूथ स्टार्ट अप के माध्यम से स्व-रोजगार शुरू करने के लिए युवाओं को वित्तीय सहायता।

जॉब पोर्टल का सृजन किया जाएगा और प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने में युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा।

ओवरसीज इम्प्लायमेंट कॉपोरेशन को फिर से शुरू किया जाएगा।

2000 बेरोजगार युवाओं को स्व-सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किया जाएगा और लगभग 5000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उन्हें विभिन्न ट्रेडस/सेक्टरस में रोजगार के योग्य बनाया जा सके।

वित्तीय सुधार/ आईटी पहलें

- विकास कार्य में सार्वजनिक भागीदारी के लिए बीम्स पोर्टल पर "EMPOWERMENT" की शुरुआत करना और कार्य के विवरण को ऑनलाइन देखने के लिए संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्र में इसे कार्यान्वित किया जा रहा है।
- ई-कुबेर भुगतान को शुरू करना- सभी कोषागारों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का कोर बैंकिंग सोल्यूशन।
- केंद्रीकृत कन्ट्रैक्ट कार्यान्वयन और भुगतान निगरानी प्रणाली की स्थापना की जाएगी।
- बोली संबंधी दस्तावेजों के मूल्यांकन परामर्शदाता रखे जाएंगे।
- वर्चुअल जांच प्रणाली को सुदृढ़ बनाते हुए ई-ऑडिट का शुरुआत की जाएगी।
- सभी सरकारी विभागों में ई-ऑफिस की शुरुआत की जाएगी।
- ऑनलाइन रियल टाइम व्यय निगरानी प्रणाली शुरू की जाएगी।

खेल संबंधी पहलें

- 8500 सहभागियों की संभावित भागीदारी के साथ फुटबॉल, कबड्डी, बॉलीबॉल, हॉकी जैसी 04 खेलों के लिए प्रीमियर लीग का आयोजन करना।
- खेलकूद संबंधी कार्यकलापों में भाग लेने के इच्छुक प्रत्येक युवा को पर्याप्त अवसर मुहैया करवाना।
- विंटर गेम्स का आयोजन करना।
- संघ राज्य क्षेत्र के उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए श्री सुरेश रैना अकादमी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करके किक्रेट को प्रोत्साहन देना।

विज्ञान और प्रोद्योगिकी

- वर्ष 2021-22 में उपयुक्त सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, पार्कों, धार्मिक स्थानों, पंचायतों, अस्पतालों में 30000 हजार सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी।
- 13.2 मेगावाट क्षमता के साथ रूफटॉप पावर सिस्टम लगाना।
- वर्ष 2021-22 के दौरान सिंचाई और पेय जल के लिए 10,000 सोलर वाटर पम्प लगाएं जाएंगे।
- आद्योगिक बॉयो टेक्नोलॉजी पार्कों को वर्ष 2021-22 में पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।

सुरक्षा पहलें

- सीमा क्षेत्रों में सामुदायिक और व्यक्तिगत बंकरों का निर्माण करना और उन्हें पूर्ण करना।
- श्रीनगर में ट्रोमा सेंटर का निर्माण।
- मॉडर्न पुलिस स्टेशन और भ्रष्टाचार-रोधी पुलिस स्टेशनों का निर्माण।
- फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला की सेवा प्रदायगी को बढ़ाने के लिए उसका उन्नयन करना।
- 02 महिला बटालियनों के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना ।
- पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी लगाने के साथ उनका डिजिटाइजेशन करना।

वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण

- वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 1 करोड़ पेड़ लगाकर ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर पौध रोपण अभियान शुरू किया जाएगा।
- वुलर लेक की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए 200 करोड़ रुपये की लागत से वुलर लेक संरक्षण और प्रबंधन कार्य योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है और इसे वर्ष 2021-22 में पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
- वुलर लेक को अतिक्रमण से बचाने के लिए उसके चारों तरफ सर्कुलर रोड का निर्माण करने के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान।

अन्य पहलें

- दावों की समय पर प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी की प्रतिपूर्ति हेतु 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
- "मिशन यूथ कार्यक्रम" के लिए 200 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए।
- जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड के पूंजीकरण के लिए 800 करोड़ का प्रावधान किया गया।
- हाइवे विश्राम स्थलों के लिए 20 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए।
- सीआरआईएफ सड़कों के लिए 300 करोड़ रुपये, पीएमजीएसवाई सड़कों के लिए 1500 करोड़ रुपये और नाबार्ड स्कीम के लिए 500 करोड़ रुपये और मुगल रोड के रख-रखाव के लिए 28 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया।
- पर्यटन के संवर्धन लिए 30 करोड़ रुपये और गोल्फ के संवर्धन के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट बढ़ाया गया।
- त्योहारों के आयोजन को प्रोत्साहित करने के लिए 200 करोड़ रुपये, सिनेमा/थिएटरों को प्रोत्साहन देने के लिए 100 करोड़ रुपये और हेरिटेज के संरक्षण के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- मानसर, सुरिनसर, वुलर, बंगस सहित नए पयर्टन सर्किटों के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इसके अलावा, नए रोपवे के लिए 20 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए।
- डीडीसी/बीडीसी कार्यालयों की स्थापना के लिए 30 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए।
- व्यवसाय पुनरुद्धार पैकेज के सभी घटकों के लिए पूरा प्रावधान किया गया है।
- वर्ष 2021-22 में 301 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ पीएमएवाई (जी) स्कीम के लिए बढ़ाया गया यूटी शेयर निर्धारित किया गया है।
- सड़कों पर पार्किंग को रोकने के लिए जाम लगने वाले क्षेत्रों में राजमार्ग पर पार्किंग स्थल बनाए गए।
- 'जल जीवन मिशन' के लिए 5212 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। "हर घर नल से जल", पानी समिति के अंतर्गत सभी जिलों को कवर किया जाएगा। गुणवत्ता सुनिश्चित करने, प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, सेवा स्तरीय बैंचमार्किंग सिस्टम शुरू करने के लिए निधियां निर्धारित की गईं।
- जल जीवन मिशन के अंतर्गत 100% यूटी शेयर निर्धारित किया गया।
- वित्तीय विभाग के अंदर थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन सिस्टम स्थापित किया जाएगा ताकि संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही सभी परियोजना का 100% वास्तविक सत्यापन सुनिश्चित हो सके।
- फिलिगिरी आर्ट को प्रोत्साहन देने के लिए स्वयं सहायता समूह स्थापित किए जाएंगे।
- सभी नगरों में ठोस कचरा प्रबंधन सुविधाओं की स्थापना की जाएंगी, सेवा स्तरीय बैंचमार्किंग सिस्टम शुरू किया जाएगा। एसडब्ल्यूएम/सीवर ट्रिटमेंट के लिए 250 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए।
- कोविड योद्धाओं के लिए अनुग्रह राहत के रूप में 40 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए।

- कृषि प्रसंस्करण जोन (फूड क्लस्टर पार्क) की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- स्कूलों, कॉलेजों में ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली, शिक्षक एवं छात्र उपस्थिति, अटेनमेंट लेवल एसेसमेंट सिस्टम, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्वच्छता, पेय जल सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- ट्रांसफारमर कट-ऑउट के लिए 50 करोड़ रुपये और स्मार्ट मीटर के लिए 20 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए।
- ग्रामीण और नगरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए पीआरआई/यूएलबी हेतु 1313 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
- मनरेगा के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र के समरूप शेयर के रूप में अतिरिक्त 200 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए।
- दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रोस्थेटिक एड्स/मोटराइज्ड ट्राई साइकिल के प्रापण हेतु 3 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए।
- पीआरआई सुरक्षा के लिए 80 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
- पुलिस हाउसिंग कॉलोनी का निर्माण करने के लिए 50 करोड़ रुपये और राहत और पुनर्वास के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
- सीमा क्षेत्रों में बकरों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधियां निर्धारित की गई।
- दो मेडीसिटीज के लिए 50 करोड़ रुपये, ड्रग-डी एडिक्शन/पुनर्वास केंद्रों के लिए 10 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकी के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
- विद्यालयों में गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 20 करोड़ रुपये, स्कूल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 करोड़ रुपये, कैरियर काउंसलिंग के लिए 5 करोड़ रुपये और स्कूलों में अतिरिक्त स्ट्रीम आरंभ करने के लिए 20 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए।
- कॉलेजों में अतिरिक्त स्ट्रीम आरंभ करने के लिए 100 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए।
- नए बनाए गए पंजीकरण विभाग के लिए 25 करोड़ रुपये, भू-अभिलेखों के डिजिटाइजेशन के लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
- स्पोर्टस लीग/कोचिंग के लिए 20 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए।
- डल विकास और संरक्षण के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
- मेट्रो कॉरपोरेशन के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
- जम्मू और श्रीनगर शहरों के लिए शहर अनुदान के रूप में 100 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए।
- श्रीनगर में आपदा राहत केंद्र की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये और जम्मू में इसकी स्थापना के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
- जम्मू एवं कश्मीर सड़क परिवहन निगम द्वारा बसों/ट्रकों की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए।
- स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए संघ राज्य क्षेत्र के समरूप शेयर के रूप में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

- मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रग्स और उपकरणों की खरीद के लिए 400 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए।
- गुज्जर और बकरवाल के लिए जनजातीय हॉस्टल/मिल्क विलेज/नोमाड शेल्टरों/लाइब्रेरी के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
- व्यावसाय पुनरुद्धार पैकेज के एक भाग के रूप में ट्रांसपोर्टरों को यात्री वाहनों के बीमाकरण हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
- व्यवसाय पुनरुद्धार पैकेज के एक भाग के रूप में ट्रांसपोर्टरों को पुराने और बेकार घोषित किए गए वाहनों को बदलने के लिए सब्सिडी के रूप में 25 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए।
- "देविका परियोजना" के लिए संघ राज्य क्षेत्र के समरूप शेयर के रूप में 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
- यूथ स्टार्ट अप/जॉब फेयर/ओवरसीज इम्प्लायमेंट कॉरपोरेशन के पुनरुद्धार के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
- 20 डीडीसी के लिए "विकास निधि'' के रूप में" 10 करोड़ रुपये प्रत्येक के हिसाब से 200 करोड़ रुपये और 285 बीडीसी के लिए "विकास निधि के रूप में" 25 लाख रुपये प्रत्येक के हिसाब से 71.25 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए।